भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1440

14 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादन में गिरावट

1440. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने संयंत्र में इस्पात की झूठी कमी दिखाने और इसका निजीकरण करने की मंशा में फरवरी, 2022 के तीसरे हफ्ते से उत्पादन को घटाने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 2022 में फरवरी से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) में किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) का निजीकरण करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): वीएसपी में कार्यात्मक आवश्यकता के कारण उत्पादन को कम किया गया है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी), जो एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, में ब्लास्ट फर्नेस मार्ग से इस्पात के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी है। कोक के उत्पादन के लिए, आरआईएनएल (वीएसपी) आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भर है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आयातित कोकिंग कोयले की उपलब्धता में भारी कमी आई है और कोकिंग कोयले की कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। तद्नुसार, कोक ओवन में कोक के उत्पादन को 25 जनवरी, 2022 से विनियमित किया गया और इसे 390 ओवन प्रतिदिन के स्तर से कम करके 270 ओवन प्रतिदिन के स्तर पर लाया गया। अतः एक ब्लास्ट फर्नेस के प्रचालन को अस्थाई रूप से रोक दिया गया था। तथापि, दो ब्लास्ट फर्नेस इष्टतम स्तर पर प्रचालनरत

हैं और फरवरी, 2022 में 14,700 टन/दिन के औसतन हॉट मेटल के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया गया था।

(घ): आरआईएनएल (वीएसपी) के निजीकरण का निर्णय सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए अधिसूचित नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के अनुरूप लिया गया है। तद्नुसार, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27.01.2021 को संपन्न हुई अपनी बैठक में निजीकरण के द्वारा रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में इसके हिस्से सहित आरआईएनएल में भारत सरकार (जीओआई) की हिस्सेदारी के 100% विनिवेश को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से इष्टतम उपयोग हेतु पूँजी का अंतःप्रवाह, क्षमता का विस्तार, प्रौद्योगिकी का संचार होगा और प्रबंधन प्रक्रियाएं बेहतर होंगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

****